

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 23 फरवरी, 2006

विषय:—वित्तीय वर्ष 2005-06 में जनपद देहरादून की नवसृजित तहसील कालसी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-मीमो/नाजिर सदर-आगणन-2005 दिनांक 23-12-2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील कालसी के आवासीय/अनावासीय भवनों के आगणन रु0 162.87 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाये गये रु0 135.44 लाख के आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये रु0 25.00 लाख (रु0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि को स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

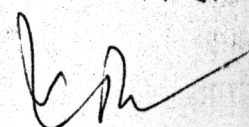
2— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4— एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2006 तक पूर्ण उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उक्त विवरण व धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।



.....(2)

- 7- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।
- 8- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी।
- 9- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
- 10- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।
- 11- यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।
- 12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-6 लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
- 13- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-85/XXVII(5)/2006 दिनांक 16 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)

अपर सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3- निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
- 4- अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
- 5- अपर सचिव, नियोजना विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 6- वित्त अनुभाग-5
- 7- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-1, कन्सट्रक्शन विंग, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 781, इन्दिरा नगर देहरादून।
- 8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)

अपर सचिव।